



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2010/माघ 7, 1931

No. 41]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2010/MAGHA 7, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 48(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची में अपर विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 और उसके सामने स्तंभ (2) से स्तंभ (14) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|--|---|--|--|-----|----------------|----------------|
| “3. अपर विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) | 01*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु. | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (8) | (9) | (10) | | | | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | | | | |

(11)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(12)

प्रोन्नति : राजभाषा खंड, विधायी विभाग का ऐसा उप-विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसा उप-विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा) जिसने उप-विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा) और सहायक विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा) की श्रेणियों में दस वर्ष सम्मिलित सेवा की हो, जिसमें से उप-विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा) की श्रेणी में कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

टिप्पणी 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 अर्थात् उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा तत्स्थानी ग्रेड वेतन/उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति—

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

आवश्यक :

- (अ) (i) किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के रूप में मानित उच्चतर शिक्षा की किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्था या विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री (एलएलएम); और

- (ii) राज्य न्यायिक सेवा का दस वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो;

या

किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में दस वर्ष तक कोई पद धारण किया हो;

या

केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्य का दस वर्ष का अनुभव हो;

या

ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो दस वर्ष तक उस रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त संस्था में दस वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो;

(12)

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) में अनुवाद करने का दस वर्ष का अनुभव हो; या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों के प्रारूपण का दस वर्ष का अनुभव हो; या

(आ)(i) किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के रूप में मानित उच्चतर शिक्षा की किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्था या विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री (एलएलबी); और

(ii) राज्य न्यायिक सेवा का बारह वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो;

या

किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में बारह वर्ष तक कोई पद धारण किया हो;

या

केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्य का बारह वर्ष का अनुभव हो;

या

ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो बारह वर्ष तक उस रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त संस्था में बारह वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो;

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) में अनुवाद करने का बारह वर्ष का अनुभव हो; या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों के प्रारूपण का बारह वर्ष का अनुभव हो;

(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) के माध्यम से उत्तीर्ण की हो अथवा माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में संबद्ध भाषा एक विषय रहा हो।

वांछनीय :

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) में विधायी प्रारूपण का पांच वर्ष का अनुभव।
2. किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के रूप में मानित उच्चतर शिक्षा की किसी संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्था या विदेशी विश्वविद्यालय से संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) के साथ बैचलर डिग्री।

टिप्पण (1) : संबद्ध भाषा की वास्तविक अपेक्षा भर्ती के समय उपरिर्दिष्ट की जाएगी।

टिप्पण (2) : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 अर्थात् वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा उसके सिवाए जहां ऐसे अनधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक जैसे ग्रेड वेतन/वेतनमान वाले एक श्रेणी में

(12)

विलय हो गया है और ऐसे विलयन की दशा में यह फायदा केवल उन्हीं पदों तक विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना 1-1-2006 से पूर्व ग्रेड का साधारण प्रतिस्थापन है, उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति
(प्रोन्नति पर विचार के लिए) में
निम्नलिखित होंगे :

- | | |
|--|----------|
| 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय | —सदस्य |
| 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय | —सदस्य |
| 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय | —सदस्य |

(14)

प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करने के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।”

[फा. सं. ए-12026/4/2004-प्रशा. 1 (वि वि)]

एम. आर. बीर, उप-सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 151, तारीख 28 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 255(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2005 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2010

G.S.R. 48(E).— In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2003, for serial number 3 relating to the post of Additional Legislative Counsel (Regional Languages Branch) and corresponding entries against it under columns (2) to (14), the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|--|--|-----------|----------------|----------------|
| "3. Additional Legislative Counsel (Regional Languages) | 01* (2010) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial | PB-4 Rs. 37400- 67000 plus Grade Pay of Rs. 8700 | Selection | Not applicable | Not applicable |

| (8) | (9) | (10) |
|----------------|----------------|----------------|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| (11) | (12) |
|---|--|
| Promotion, failing which by deputation. | <p>Promotion : Deputy Legislative Counsel (Regional Languages Branch) of Official Languages Wing, Legislative Department with five years' regular service in the grade failing which Deputy Legislative Council (Regional Languages Branch) with ten years' combined regular service in the grades of Deputy Legislative Council (Regional Languages Branch) and Assistant Legislative Counsel (Regional Languages Branch) with at least two years' regular service in the grade of Deputy Legislative Counsel (Regional Languages Branch).</p> |

Note (1) :—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note (2):—For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission's recommendations has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation : Officers under the Central or State Government—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the Parent Cadre or Department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the PB-3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 7600/- or equivalent in the Parent Cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :

Essential :

A.(i) Master's Degree in Law (LLM) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; and

(12)

(ii) should be a member of State Judicial Service for a period of ten years;

or

should have held a post in the legal department of a State Government for ten years;

or

should be a Central Government servant who has had experience in legal affairs for ten years;

or

should be a qualified legal practitioner who has practised as such for ten years;

or

should be a teacher of law for ten years in a recognised institution;

or

should have ten years' experience of translation into the language (one of the languages, other than Hindi, mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned of statutes, statutory rules and orders in Central or State Governments;

or

should have ten years' experience of drafting of statutes in the Central or State Governments;

or

B. (i) Bachelor's Degree in Law (LL.B) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government;

(ii) should be member of State Judicial Service for a period of twelve years;

or

should have held a post in the legal department of a State Government for twelve years;

or

should be a Central Government servant who has had experience in legal affairs for twelve years;

or

should be a qualified legal practitioner who has practised as such for twelve years;

or

should be a teacher of law for twelve years in a recognised institution;

or

should have twelve years' experience of translation into the language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned of statutes, statutory rules and orders in Central or State Government;

or

should have twelve years' experience of drafting of statutes in the Central or State Government;

(iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or Institution through medium of language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned or had offered the language concerned as a subject in Secondary School Examination or any higher examination.

Desirable :

1. Five years' experience of legislative drafting in the language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned in Central or State Government.

2. Bachelor's degree from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government with the language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned as a subject or medium at degree level.

Note (1).—The exact requirement of the language concerned shall be indicated at the time of recruitment.

Note (2).— For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the said Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay/pay scale, and in the case of such merger this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement of the grade prior to 01-01-2006 without any upgradation.

Note :—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

13

14

**Group 'A' Departmental Promotion Committee
(for considering promotion)**

- | | |
|--|-----------|
| 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission | —Chairman |
| 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice | —Member |
| 3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice | —Member |
| 4. Joint Secretary and Lagislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice | —Member |

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation."

[F. No. A-12026/4/2004-Admn.1(LD)]

M.R. BEERH, Dy. Secy.

Note :—The principal rules were published *vide* G.S.R. 151 dated the 28th March, 2003 in Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* number G.S.R. 255(E), dated the 21st April, 2005.

